शिमला शहर के लिए शहरी अवस्थापना औरषासन(जेएनयूआरएम)के अर्न्तगत निम्नलिखित 7 परियोजना स्वीकृत की गई हैं जिस कि सूची इस प्रकार से हैः–

1. शिमला शहर के लिए ठोस कचरा प्रबन्धन।
2. औक्लैंड हाउस स्कूल शिमला के नजदीक सुरंग को चौडा करना व नीचे करना तथा पुल का निर्माण करना।
3. शिमला शहर में बसों की खरीद करना।
4. शिमला शहर में पानी की वितरण प्रणाली का जीर्णोद्वार करना।
5. शिमला शहर की मल निकासी योजना के छुटे हुए क्षेत्र व पाईप लाइन व क्षतिग्रस्त मल निकासी पाईप लाइन का सुधार।
6. शिमला मे ई गर्वनैंस की स्थापना।
7. गांव भरियाज, तहसीन व जिला षिमला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए सेनेटरी लैंडफिल साइट का प्रबन्धन।

1. **ठोस अपषिट प्रबन्धन नगर निगम**, षिमला की प्राथमिक गतिविधियों में से एक है। यह परियोजना 1604 लाख रूप्ये की राषि के साथ मार्च, 2007 में जेएनएनयूआरएम योजना के तहत् स्वीकृत की गई। राषि 1604 लाख रूपये में भारत सरकार के 80% के प्रावधान के साथ(1283.20 लाख)]10%राज्य शेयर;160.40 लाख) और यूएलबी शेयर (160.40 लाख) 10% इस योजना के अर्न्तगत अनुमोदित किये गये । इस परियोजना के अन्तर्गत 10 घटक थे, जिनमें से एक घटक अपषिष्ट उपचार और निपटान की सुविधा एकीकृत है जिसकी सविस्तार जानकारी इस प्रकार से हैः– वैष्विक बोलियां आमन्त्रित करने के बाद जुलाई, 2010 के महीने में घटक यानि समन्वित अपषिष्ट उपचार और निपटान की सुविधा को मैसर्ज हैंजर बायोटेक ऊर्जा प्राईवेट लिमिटिड मुंबई को 20 साल की अवधि के लिए बीओटी आधार पर आंबटित किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कम्पनी 150 रू0 प्रति मिट्रिक टन की दर से ठोस अपषिष्ट (एमएसडब्लयू) के प्रसंस्करण व ढोने वाले शुल्क के रूप में लेगी। इसके इलावा अन्य विभिन्न घटकों पर राषि रू0 517.04 लाख व्यय किया गया है।
2. **ऑकलैंड हाउस स्कूल षिमला** के नजदीक सुरंग को चौडा करना व नीचे करना तथा पुल का निर्माण करनाः– इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत रू0 1009.06 लाख की लागत के साथ अनुमोदित किया गया । इस योजना का कार्य हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्य को करने मे 908.16 लाख का व्यय किया गया है।
3. **शिमला शहर में बसों की खरीद करना** :– इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत रू0 760.19 लाख की लागत के साथ अनुमोदित किया गया। इस योजना के अंर्तगत 75 बसों को HRTC द्वारा खरीदा गया है।
4. **शिमला शहर में पानी की वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार करना** इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अर्न्तगत 7236.00 लाख रू0 की परियोजना रिपोट दिनांक 20.02.2009 को स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 1447.20 लाख रुपये नगर निगम शिमला को पहली

किश्त दिनांक 16.08.2010 को प्राप्त हुई है। दिनांक 09.03.2011 को प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पानी की वितरण प्रणाली तथा सिवरेज प्रणाली जिसकी डीपीआर 2010 मे स्वीकृत की गई थी दोनो को इकटठा करके पी0पी0पी0 मोड के आधार पर निमार्ण किया जाएं।अतः निर्णय अनुसार पी0पी0पी0 के आधार पर कार्य करने हेतु M/s Feedback Infrastructure Pvt. Ltd. dks RFP तैयार करने हेतू Transaction Advisor चयंनित किया गया। अतः पी0पी0पी0 के आधार पर निमार्ण करने हेतू पहली बार एक ही कम्पनी द्वारा निविदांए प्राप्त होने पर दिनांक 05.012.2012 को दोबारा से निविदांए बुलाई गई इस बार भी एक ही निविदांए प्राप्त हुई। अतः एक निविदा को खोलनें हेतू मामला सरकार को भेजा गया था। दिनांक 31.07.2013 को निर्णय लिया गया कि दोनो परियोजनाओं को ईपीसी मोड पर लागू किया जाएगा तथा यह निर्णय लिया गया कि सिचाई एंव जन स्वास्थय विभाग दोनो परियोजना कि संषोधित परियोजना रिर्पोट नई दरो पर तैयार करके धन की उपलब्धता हेतू तथा 3 साल बढाने के लिए भारत सरकार को भेजे। उपरोक्त निर्णय अनुसार जल आपूर्ति की संषोधित परियोजना रिर्पोट 136.93 करोड़ की बना कर भारत सरकार को भेजी गई। परन्तु केन्द्र सरकार के चुनाव घोषणा होने तथा modal Code of Conduct के कारण DPR को वापिस भेज दिया गया। इस परियोजना को पूरा करने की समय अवधि भी मार्च 2014 थी। दिनांक 14.10.2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी की अध्यक्षता मे कि गई मिट्रिग मे यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम षिमला के पास जो राषि इस परियोजना हेतू प्राप्त हुई है, उसे परियोजना रिपोट के धटको के अनुसार खर्च किया जाए। तथा इस निर्णय के अनुसार यह 22.58 करोड़ रुपये की राषि सिचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को परियोजना रिपोट के घटको के अनुसार खर्च करने हेतु दिनांक 18.03.2016 को निदेषक शहरी विकास विभाग को स्थांनतरित की गई है। अब नगर निगम के पास रुपये 2,67,12,848 राषि शेष है। जिसे भी परियोजना रिर्पोट के अनुसार स्वीकृत घटको पर खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस परियोजना पर नगर निगम षिमल द्वारा राषि रू0 83.79 लाख व्यय किया गया है। जिसमें कि पी0पी0पी0 के आधार पर दोनो परियोजनाओं **(शिमला शहर में पानी की वितरण प्रणाली के जीर्णोद्वार व मल निकासी योजना)**Transction Advisor का खर्चा तथा संषोधित परियोजना रिर्पोट को तैयार करने मे Consultant को दी गई राषि तथा निविदांए बुलाने के लिए विज्ञापन का खर्चा व अन्य खर्चे शामिल है। यह परियोजना अब शिमला जल प्रबधन द्वारा की जा रही है तथा नगर निगम द्वारा शेष बची हुई राशि को शिमला जल प्रबधन निगम को स्थानातरित करदी गई है।

5. **शिमला शहर की मल निकासी योजना के छुटे हुए क्षेत्र व पाईप लाईन तथा क्षतिग्रस्त कल निकासी पाईप लाईन के सुधार** इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अर्न्तगत 5474.00 लाख रू0 की परियोजना रिपोट दिनांक जनवरी 2010 को स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 970.00 लाख रुपये नगर निगम शिमला को पहली किषत दिनांक 05.05.2010 को प्राप्त हुई है। दिनांक 09.03.2011 को प्रदेष सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पानी की वितरण प्रणाली तथा सिवरेज प्रणाली जिसकी डीपीआर 2010 मे स्वीकृत की गई थी दोनो को इकटठा करके पी0पी0पी0 मोड के आधार पर निमार्ण किया जाएं।अतः निर्णय अनुसार पी0पी0पी0 के आधार पर कार्य करने हेतु M/s Feedback Infrastructure Pvt. Ltd. को RFP तैयार करने हेतू ज्तंदेंबजपवद Advisor चयंनित किया गया। अतः पी0पी0पी0 के आधार पर निमार्ण करने हेतू पहली बार एक ही कम्पनी द्वारा निविदांए प्राप्त होने पर

दिनांक 05.012.2012 को दोबारा से निविदांए बुलाई गई इस बार भी एक ही निविदांए प्राप्त हुई। अतः एक निविदा को खोलनें हेतू मामला सरकार को भेजा गया था। दिनांक 31.07.2013 को निर्णय लिया गया कि दोनो परियोजनाओं को ईपीसी मोड पर लागू किया जाएगा तथा यह निर्णय लिया गया कि सिचाई एंव जन स्वास्थय विभाग दोनो परियोजना कि संषोधित परियोजना रिर्पोट नई दरो पर तैयार करके धन की उपलब्धता हेतू तथा 3 साल बढाने के लिए भारत सरकार को भेजे। उपरोक्त निर्णय अनुसार जल आपूर्ति की संषोधित परियोजना रिर्पोट 170.35 करोड़ की बना कर भारत सरकार को भेजी गई। परन्तु केन्द्र सरकार के चुनाव घोषणा होने तथा modal Code of Conduct के कारण क्च् को वापिस भेज दिया गया। इस परियोजना को पूरा करने की समय अवधि भी मार्च 2014 थी। दिनांक 14.10.2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव शहरी की अध्यक्षता मे कि गई मिट्रिग मे यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम षिमला के पास जो राषि इस परियोजना हेतू प्राप्त हुई है, उसे परियोजना रिर्पोट के धटको के अनुसार खर्च किया जाए तथा इस निर्णय के अनुसार यह 19,42,02,958/. करोड़ रुपये की राशि सिचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को परियोजना रिपोट के घटको के अनुसार टूटु मे प्रस्तावित सीवरेज परियोजना मे खर्च करने हेतु दिनांक 02.01.2016 को निदेषक शहरी विकास विभाग को स्थांनतरित की गई कि अब नगर निगम के पास रुपये 53,87,204/- राशि शेष है। जिसे भी परियोजना रिपोट के अनुसार सविकृत घटको पर खर्च किया जाएगा। यह परियोजना अब शिमला जल प्रबधन द्वारा की जा रही है तथा नगर निगम द्वारा शेष बची हुई राशि को शिमला जल प्रबधन निगम को स्थानातरित करदी गई है।

6. **शिमला के ठोस कचरा प्रबन्धन प्लांट के लिए सेनेटरी लैंडफिल साईटका प्रबन्धन** करना इस परियोजना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के अर्न्तगत 1050.62 लाख रू0 की परियोजना रिपोट 12.03. 2012 स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 210.13 लाख रुपये नगर निगम षिमला को पहली किषत दिनांक 27.04.2013 और 27.08.2014 को 52ण्33 लाख और 157.60 लाख इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतू दिनांक 07.11.2012 को पहली बारे पी0पी0पी0 के आधार पर निविदांए बुलाई गई परन्तु एक ही निविदा होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा तथा मार्च 2013 मे दोबारा निविदांए बुलाई गई दोबार से एक ही निविदा प्राप्त हुई। तथा इसकी दर ज्यादा होने के कारण इसे प्रदेष सरकार को भेजा गया लेकिन प्रदेष सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 05.11.2013 के अनुसार इसकी दरें ज्यादा होन पर रद्व कर दिया गया । भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.05.2014 को के द्वारा इसें non stater Project मे लिया गया। इस सम्बन्ध मे भारत सरकार से समय अवधि बढाने के लिए पत्र लिखा गया लेकिन दिनांक 28.05.2014 प्रदेष सरकार से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें GoI ने समय बढानें से इन्कार कर दिया तथा कहा गया कि प्रदेश सरकार अपने खर्चे पर परियोजना को पूरा करें। दिनांक 14.10.2015 को अतिरिक्त मुख्य सचित शहरी की अध्यक्षता मे कि गई मिट्रिग मे यह निर्णय लिया गया कि प्राप्त राषि को परियोजना रिर्पोट के अनुसार ठोस कचरा प्रबन्धन प्लांट के साथ सैनिटर लैड़फिल साईट के निमार्ण हेतू खर्च्र किया जाएं इस निर्णय के अनुसार सैनिटर लैड़फिल साईट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तथा इस परयिोजना पर राषि रू0 31.09 लाख व्यय किए गए है। जिसमें कि परियोजना रिर्पोट बनाने का खर्चा और निविदाओ के विज्ञापन का खर्चा व सैन्टेरी लैडफिल साईट के लिए

दिवार लगाने का खर्चा शामिल है। यह परियोजना अब शिमला जल प्रबधन द्वारा की जा रही है तथा नगर निगम द्वारा शेष बची हुई राशि को शिमला जल प्रबधन निगम को स्थानातरित करदी गई है।

7. **नगर निगम षिमला में ई–गर्वनैंस** की स्थापना नगर निगम षिमला में ई–गर्वनैंस की स्थापना हेत भारत सरकार द्वारा 11.20 करोड़ की डीपीआर रू024.02.2012 मे स्वीकृति की गई थी। इस परियोजना के अर्न्तगत भारत सरकार से 224 लाख रुपये की पहली किषत प्राप्त हुई है इस परयिोजना के कियान्वयन हेतू नगर निगम द्वारा निविदाऐं आमन्त्रित करने के उपरान्त M/s ABM Knowledgeware Ltd., ABM House, Plot No.268, Linking Road, Bandra (West), Mumbai- 40050, India कम्पनी को मार्च 2014 मे दे दिया गया था। परन्तु भारत सरकार द्वारा और राषि न मिलने के कारण सम्मबधित कम्पनी को प्राप्त राशि के अन्दर कार्य का स्कोप को धटा करके इसे करने को कहा गया लेकिन ABM Knowledge ware Ltd. की तरफ से कोई प्रतिकिया प्राप्त नहीं हुई अतः अब माननीय सदन ने दिनांक 30.06.2016 मे यह निर्णय लिया कि प्राप्त राशि के अनुसार यह कार्य NIC द्वारा किया जाएं। इस बारे मे NIC से आगामी कार्यवाही हेतू पत्राचार किया गया है।

ई0गवर्नैंस प्रोजैक्ट – नवीनतन स्थिति

नगर निगम षिमला में ई0गवर्नैंस प्रोजैक्ट को कार्यन्वित करने के लिये रू0 11.20 करोड़ की डी0 पी0 आर0 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 24.02.2012 को स्वीकृत कर दी गई है। प्रोजेक्ट की कीमत का 80 प्रतिषत् शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, 10 प्रतिषत् हिमाचल सरकार द्वारा व शेष 10 प्रतिषत् नगर षिमला द्वारा वहन किया जायेगा। ई0गवर्नैंस प्रोजैक्ट का कार्यान्वित करने का मूल ध्येय नगर निगम की कार्य क्षमता में सुधार, कार्य में विलम्बता को दूर करना व उत्तरदायित्वता, निष्पक्षता, पारदर्षिता को बढ़ावा देना है, व जनता के कीमती समय को बचाते हुए, तीव्र गति से सेवाएं प्रदान करना है। ई0गवर्नैंस प्रोजैक्ट के अन्तर्गत निम्न 22 माडयूलस् शामिल किये गए हैः–

1. अकांऊटस्
2. ऑडिट विभाग
3. बिल्डिंग परमिषन
4. लैण्ड एण्ड ईस्टेट मैनेजमैन्ट
5. फलीट व्हीकल मैनेजमैन्ट सिस्टम
6. हयूम्न रिसोर्स मैनेजमैन्ट सिस्टम व इम्पलोई सैल्फ सर्विस
7. परचेज
8. इनवैन्टरी मैनेजमैन्ट सिस्टम
9. एस्सट मैनेजमैन्ट सिस्टम
10. जन्म व मृत्यु पंजीकरण
11. लाईसैन्स फूड व मार्किट
12. सोलिड वेस्ट मैनेजमैन्ट
13. ग्रीवैन्स मैनेजमैन्ट सिस्टम
14. वैब पोर्टल
15. सीटिजन सर्विस सैन्टर
16. लीगल डिपार्टमैन्ट
17. ई–प्रोक्यूर इन्टीग्रेषन
18. प्रोजैक्ट मैनेजमैन्ट सिस्टम / ईन्जीनियरिंग विंग
19. वैलफेयर स्कीम
20. प्रोपटी टैक्स
21. रैजीडैन्ट आई डी रजिस्ट्रेषन
22. वाटर एण्ड बिलिंग

अतः लोग ई0गवर्नैंस प्रोजैक्ट के कार्यान्वित होने पर ऑन लाईन बिलिंग की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं व अपने खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के सन्दर्भ में SystemIntegrator के चयन के लिये नगर निगम षिमला द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई थी। टैन्डर के आधार पर एल–1 बिडर मै0 ए0बी0एम0 नोलेजवेयर मुम्बई को चुना गया व यह कार्य रुपये 10,71,00,000/– में दिनांक 23.03.2014 को अवार्ड किया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार से प्रोजैक्ट के अंतर्गत पहली किस्त रुपये 2,66,83,626/– प्राप्त हो चुकी है। परन्तु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिषा निर्देषों अनुसार, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अंतर्गत सभी स्वीकृत प्रोजैक्ट मार्च 2014 तक पूर्ण होने थे।

उपरोक्त को मध्यनजर रखते हुए, प्राप्त निधि रुपये 2,66,83,626/– का अनुकूलतम उपयोग करने हेतू अतिरिक्त मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग हि0 प्र0 की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें उपरोक्त प्रोजैक्ट को रुपये 2,66,83,626/– में ही नगर निगम षिमला में implement किये जाने का निर्णय लिया गया व कम्प्युटर हार्डवेयर को ऐग्रीमैंट से हटा दिया गया। मै0 ए0बी0एम0 नोलेजवेयर मुम्बई उपरोक्त अनुसार इस कार्य को करने के लिये सहमत भी हो गया था। परन्तु जो ड्राफट ऐग्रीमैंट Committee Members i.e. DoIT, MCS, NIC and representative of M/S ABM ने पुनः निरीक्षण किया था, उस पर मै0 ए0बी0एम0 नोलेजवेयर मुम्बई की कोई भी प्रतिक्रिया नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई। इससे यह प्रतीत हुआ कि मै0 ए0बी0एम0 नोलेजवेयर मुम्बई इस प्रोजैक्ट में रुचि नहीं ले रहा हैं, अतः नगर निगम के माननीय सदन द्वारा प्रस्ताव न0 3(27) दिनांक 30.06.2016 पारित किया गया कि यह कार्य NIC, Shimla HP के द्वारा करवाया जाये, अतः NIC, Shimla H.P. से इस सम्बन्ध में कार्य शीघ्र आरम्भ करने बारे पत्राचार शुरु कर दिया गया है।

इसी दौरान नगर निगम षिमला को निम्न 09 प्रकार की G2C Services का प्रस्ताव performa invoice amounting to Rs. 25,71,468.63/- (Rupees Twenty Five LakhSeventy OneThousand Four Hundred Sixty Eight and Sixty Three Paise only) सहित सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग हि0 प्र0 से प्राप्त हुआ था।

LIST OF 09 NO. MODULES TO BE DEVELOPED BY DOIT

S. No.	Name of Service
1	Water Billing
2	Water Supply Connection
3	Property Tax Payment
4	Sewerage Connection
5	NOC of Electricity
6	Permission of Dumping
7	Permission of Canopy
8	Rent and Lease
9	Permission for Tree cutting / falling

अतः नगर निगम षिमला के माननीय सदन द्वारा प्रस्ताव न0 3(1) दिनांक 30.06.2017 को उपरोक्त 09 प्रकार की G2C Services को नगर निगम षिमला में सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग हि0 प्र0 द्वारा Develop and implement करवाने का निणर्य लिया। इस उपरान्त इस कार्य को सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग हि0 प्र0 से करवाने के लिये पत्राचार किया गया व उपरोक्त राषि रुपयs Rs. 25,71,468.63/- (Rupees Twenty Five LakhSeventy One Thousand FourHundred Sixty Eight and Sixty Three Paise only) का भुगतान दिनांक 21.11.2017 को RTG के माध्यम से सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग, षिमला, हि0प्र0 को कर दिया गया है व उपरोक्त वर्णित क्र0 सं0 1 से 7 तक की G2C Services को सूचना व प्रौद्योगिकि विभाग हि0 प्र0 द्वारा Develop कर दी गई हैं।